



2026:AHC:45559

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - **924/2026**

वीरेन्द्र सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उप-संचालक चकबंदी, आजमगढ़ एवं 5 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कृष्ण माधव पाण्डेय, मेराज अहमद खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. तत्काल रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग के लिए दायर की गई है:-

"एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो उप-संचालक चकबंदी आजमगढ़ को निर्देश दे कि वे उनके न्यायालय में यू.पी. सी.एच. अधिनियम, 1953 की धारा 48(1) के तहत लंबित पुनरीक्षण वाद संख्या 0176/2026, कंप्यूटर केस संख्या 20265415600000176 (नरेन्द्र सिंह और अन्य बनाम रवीन्द्र और अन्य) में दायर स्थगन आवेदन दिनांक 30.01.2026 को एक निर्दिष्ट समयबद्ध अवधि के भीतर या इस माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार त्वरित गति से निस्तारित करें।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले को शीघ्र तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।
4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। उप-संचालक चकबंदी, आजमगढ़ (प्रतिवादी संख्या 1) को यह निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से उपरोक्त स्थगन आवेदन को शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर तय करें।
5. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

फरवरी 27, 2026

वी.आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"